

UNFCCC में पार्टियों का 28वाँ सम्मेलन

प्रलिस के लिये:

[पार्टियों का 28वाँ सम्मेलन \(COP28\)](#), [जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय \(UNFCCC\)](#), [लॉस एंड डैमेज \(L&D\) फंड](#), [अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य](#), [ग्लोबल स्टॉकटेक ड्राफ्ट](#), [पेरिस समझौता](#)

मेन्स के लिये:

जलवायु परिवर्तन और उसका प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण तथा क्षरण, पार्टियों का 28वाँ सम्मेलन (COP28)

[स्रोत: द हिंदू](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय \(UNFCCC\)](#) के लिये [पार्टियों का 28वाँ सम्मेलन \(कॉन्फरेंस ऑफ पार्टिज़-28\)](#) दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था।

COP28 की मुख्य वशिषताएँ क्या हैं?

■ लॉस एंड डैमेज (L&D) फंड:

- COP28 के सदस्य देश जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर रहे देशों को प्रतपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य [लॉस एंड डैमेज \(L&D\) फंड](#) को संचालित करने के लिये एक समझौते पर पहुँचे।
 - UNFCCC तथा [पेरिस समझौते](#) के अनुरूप, [वशिव बैंक](#) चार वर्षों के लिये फंड/नधिका "अंतरमि मेज़बान" होगा।
- सभी विकासशील देश आवेदन करने के पात्र हैं तथा प्रत्येक देश को स्वेच्छा से योगदान देने के लिये "आमंत्रित" किया जाता है।
 - [अल्प विकसित देशों तथा लघु द्वीपीय विकासशील देशों](#) के लिये फंड का एक वशिषिट प्रतशित नरिधारित किया गया है।

■ ग्लोबल स्टॉकटेक ड्राफ्ट:

- [ग्लोबल स्टॉकटेक \(GST\)](#) वर्ष 2015 में संपन्न हुए [पेरिस समझौते](#) के तहत स्थापित एक आवधिक समीक्षा तंत्र है।
- GST के चौथे मसौदे का अनावरण COP28 में किया गया।
 - मसौदे में वैश्विक तापमान वृद्धिको 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखने के लिये आठ कदम प्रस्तावित हैं:
 - वशिष स्तर पर [नवीकरणीय ऊर्जा](#) क्षमता को तीन गुना करना तथा वर्ष 2030 तक ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को दोगुना करना;
 - [CC\(U\)S तकनीक रहित कोयला वदियुत संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना](#) तथा नवीन व नरिबाध कोयला वदियुत उत्पादन की अनुमति पर सीमाएँ नरिधारित करना;
 - [शुद्ध-शून्य उत्सर्जन ऊर्जा](#) प्रणालियों को प्राप्त करने तथा सदी के मध्य से पहले अथवा उसके आसपास तक कम एवं शून्य-कार्बन ईंधन का उपयोग करने के लिये वशिषव्यापी प्रयासों को आगे बढ़ाना;
 - ऊर्जा प्रणालियों में [CC\(U\)S तकनीक रहित जीवाश्म ईंधन के प्रतसि्थापन की दशिा में प्रयासों को बढ़ाने के लिये शून्य एवं कम उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों](#) में तेज़ी लाना, जसिमें अन्य मुद्दों के साथ-साथ, नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, कमी व नषिकासन प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं, जनिमें [कार्बन कैप्चर](#) तथा उपयोग व भंडारण एवं कम कार्बन [हाइड्रोजन उत्पादन](#) शामिल हैं।
 - वजिज्ञान को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2050 तक, उससे पूर्व अथवा उसके आसपास शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिये, [जीवाश्म ईंधन की खपत एवं उत्पादन दोनों को उचित, व्यवस्थित व न्यायसंगत तरीके से कम करना](#);
 - वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर वशिष रूप से मिथेन उत्सर्जन को कम करना;
 - बुनियादी ढाँचे के विकास और शून्य तथा [कम उत्सर्जन वाले वाहनों](#) को तेज़ी से अपनाने के साथ कई उपायों के माध्यम से सड़क परिवहन से उत्सर्जन कटौती में तेज़ी लाना;
 - [अप्रभावी जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना](#), जो फज़िलखर्ची को बढ़ावा देता है और ऊर्जा नरिधनता या सरिफ बदलावों को संबोधित नहीं करता है।
- विकासशील और गरीब देश [COP28 में ग्लोबल स्टॉकटेक \(GST\) के नवीनतम मसौदे पर असंतोष व्यक्त कर रहे हैं](#) और महत्त्वपूर्ण

बदलावों की मांग कर रहे हैं।

- मसौदे में "जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने" का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें कोयले के उपयोग पर कड़ी आपत्ति शामिल है। यह भारत और चीन जैसे अत्यधिक कोयले पर निर्भर रहने वाले देशों के लिये समस्याग्रस्त है।
- भारत ने कोयले के उपयोग के संदर्भ में 'रैपडि' शब्द को शामिल करने पर कड़ा वरिध जताया है। यह ग्लासगो में COP26 में हुई वार्ता के विपरीत है, जहाँ भारत और चीन ने कोयला चरण समाप्ति शब्द को 'चरणबद्ध तरीके से कम' करने के लिये काम किया था।
 - भारत, जो अपनी लगभग 70% बजिली उत्पादन के लिये कोयले पर निर्भर है, का लक्ष्य कोयला आधारित बजिली उत्पादन क्षमता में 17 गीगावाट जोड़ने का है।
 - भारत का तर्क है कि उसे अपनी विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिये कोयले का उपयोग जारी रखने की जरूरत है और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) का पालन करने के महत्त्व पर जोर देता है।
- विकासशील देश अमीर देशों से नकारात्मक कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का आह्वान करते हैं, न कि 2050 तक शुद्ध शून्य तक पहुँचने का। वे जलवायु परिवर्तन से निपटने में समान लेकिन विभिन्न ज़िम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के सिद्धांतों पर भी बल देते हैं।
- विकासशील देशों का तर्क है कि अमीर देश, जिन्होंने वैश्विक कार्बन बजट का 80% से अधिक उपभोग किया है, उन्हें विकासशील देशों को भविष्य के उत्सर्जन में उनका उचित हिस्सा प्रदान करना चाहिये।
- वैश्विक नवीकरणीय और ऊर्जा दक्षता प्रतियोगिता:
 - प्रतियोगिता में कहा गया है कि हस्ताक्षरकर्त्ता 2030 तक दुनिया की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को कम से कम 11,000 गीगावाट तक तीन गुना करने और 2030 तक हर साल ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को लगभग 2% से दोगुना करके 4% से अधिक करने तथा मलिकर काम करने के लिये प्रतियोगिता है।
- COP28 के लिए वैश्विक शीतलन प्रतियोगिता:
 - इसमें 66 राष्ट्रीय सरकारी हस्ताक्षरकर्त्ता शामिल हैं जो 2050 तक 2022 के स्तर के सापेक्ष वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में शीतलन-संबंधी उत्सर्जन को कम से कम 68% कम करने के लिये मलिकर काम करने के लिये प्रतियोगिता है।
- जलवायु वित्त:
 - व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) का अनुमान है कि जलवायु वित्त के लिये नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य (NCQG) के तहत धनी देशों पर 2025 में विकासशील देशों का 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर बकाया है।
 - 2015 में पेरिस समझौते के तहत विकासित देशों द्वारा NCQG की पुष्टि की गई थी।
 - इसका लक्ष्य 2025 से पूर्व एक नया सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित करना है। यह लक्ष्य प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर से शुरू होगा।
 - इसमें शमन के लिये 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर, अनुकूलन के लिये 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर और हानि क्षतिपूर्ति के लिये 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल हैं।
 - वर्ष 2030 तक यह आँकड़ा बढ़कर 1.55 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है।
 - प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वर्तमान जलवायु वित्त लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है, और विकासशील देश ऋण संकट का सामना कर रहे हैं।
 - विशेषज्ञ संरचनात्मक मुद्दों के समाधान और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिये वैश्विक वित्तीय ढाँचे में सुधार का आह्वान करते हैं।
- अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य (GGA):
 - अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य (GGA) पर प्रारंभिक डेटा पेश किया गया था। इसकी स्थापना पेरिस समझौते के तहत 1.5/2°C लक्ष्य के संदर्भ में देशों की अनुकूलन आवश्यकताओं के प्रति जागरूकता एवं वित्तपोषण बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को बेहतर करने के लिये की गई थी।
 - प्रारूप पाठ महत्त्वपूर्ण मुद्दों को हल करता है:
 - जलवायु-प्रेरित जल की कमी की समस्या का हल।
 - जलवायु-अनुकूल भोजन और कृषि उत्पादन।
 - जलवायु-संबंधी स्वास्थ्य प्रभावों के वृद्धि समुत्थान शक्ति को मज़बूत करना।
- ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी की घोषणा:
 - COP28 में शुरू की गई घोषणा का लक्ष्य वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करना है।
 - 22 राष्ट्रीय सरकारों द्वारा समर्थित घोषणा में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के शेयरधारकों से समर्थन का आह्वान किया गया है। यह शेयरधारकों को ऊर्जा ऋण नीतियों में परमाणु ऊर्जा को शामिल करने का समर्थन करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- पावरगि पासट कोल एलायंस (PPCA):
 - PPCA राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय सरकारों, व्यवसायों एवं संगठनों का एक गठबंधन है जो निर्बाध कोयला बजिली उत्पादन से स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण को आगे बढ़ाने के लिये कार्य कर रहा है।
 - COP28 में PPCA ने नई राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय सरकारों का स्वागत किया तथा स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों का आह्वान किया।
- कोयला संक्रमण त्वरक:
 - फ्रांस ने विभिन्न देशों और संगठनों के सहयोग से कोयला संक्रमण त्वरक की शुरुआत की।
 - उद्देश्यों में कोयले से स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन की सुविधा के लिये ज्ञान-साझाकरण, नीति डिज़ाइन और वित्तीय सहायता शामिल है।
 - इस पहल का उद्देश्य प्रभावी कोयला परिवर्तन नीतियों के लिये सर्वोत्तम प्रथाओं और प्राप्त सीख का लाभ उठाना है।
- जलवायु कार्रवाई के लिये उच्च महत्वाकांक्षा बहुस्तरीय भागीदारी गठबंधन (CHAMP):
 - कुल 65 राष्ट्रीय सरकारों ने जलवायु रणनीतियों की योजना, वित्तपोषण, कार्यान्वयन एवं निगरानी में उपराष्ट्रीय सरकारों के साथ, जहाँ लागू और उचित हो, सहयोग बढ़ाने के लिये CHAMP प्रतियोगिताओं पर हस्ताक्षर किये।
- COP28 में भारत के नेतृत्व वाली पहल:
 - ग्लोबल रिवर सटीज अलायंस (GRCA):

- इसे भारत सरकार के [जल शक्ति मंत्रालय](#) के तहत [राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन \(NMCG\)](#) के नेतृत्व में COP28 में लॉन्च किया गया था।
 - GRCA एक अनूठा गठबंधन है जो विश्व के 11 देशों के 275+ नदी-शहरों को कवर करता है।
 - भागीदार देशों में मसिर, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान एवं नीदरलैंड से हेग (डेन हाग), ऑस्ट्रेलिया से एडलिड और हंगरी के स्ज़ोलनोक के नदी-शहर शामिल हैं।
 - GRCA **सतत नदी-केंद्रीत विकास** तथा जलवायु लचीलेपन में **भारत की भूमिका** पर प्रकाश डालता है।
- **हरति ऋण पहल:**
- GRCA मंच ज्ञान के आदान-प्रदान, नदी-शहर के जुड़ाव एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार की सुविधा प्रदान करेगा।
 - भारत ने नवीन **पर्यावरण कार्यक्रमों और उपकरणों के आदान-प्रदान तथा एक भागीदारीपूर्ण वैश्विक मंच बनाने के लिये** यहाँ COP28 में ग्रीन क्रेडिट पहल शुरू की।
 - इस पहल की दो मुख्य प्राथमिकताएँ [जल संरक्षण](#) और [वनीकरण](#) हैं।
 - इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश के सामने आने वाले **जलवायु संबंधी मुद्दों में बदलाव** लाने वाले बड़े नगिर्मों और नजी की कंपनियों को प्रोत्साहित करके वृक्षारोपण, जल संरक्षण, [टिकाऊ कृषि](#) एवं [अपशिष्ट प्रबंधन](#) जैसी सवैच्छिक **पर्यावरणीय गतिविधियों को बढ़ावा देना** है।





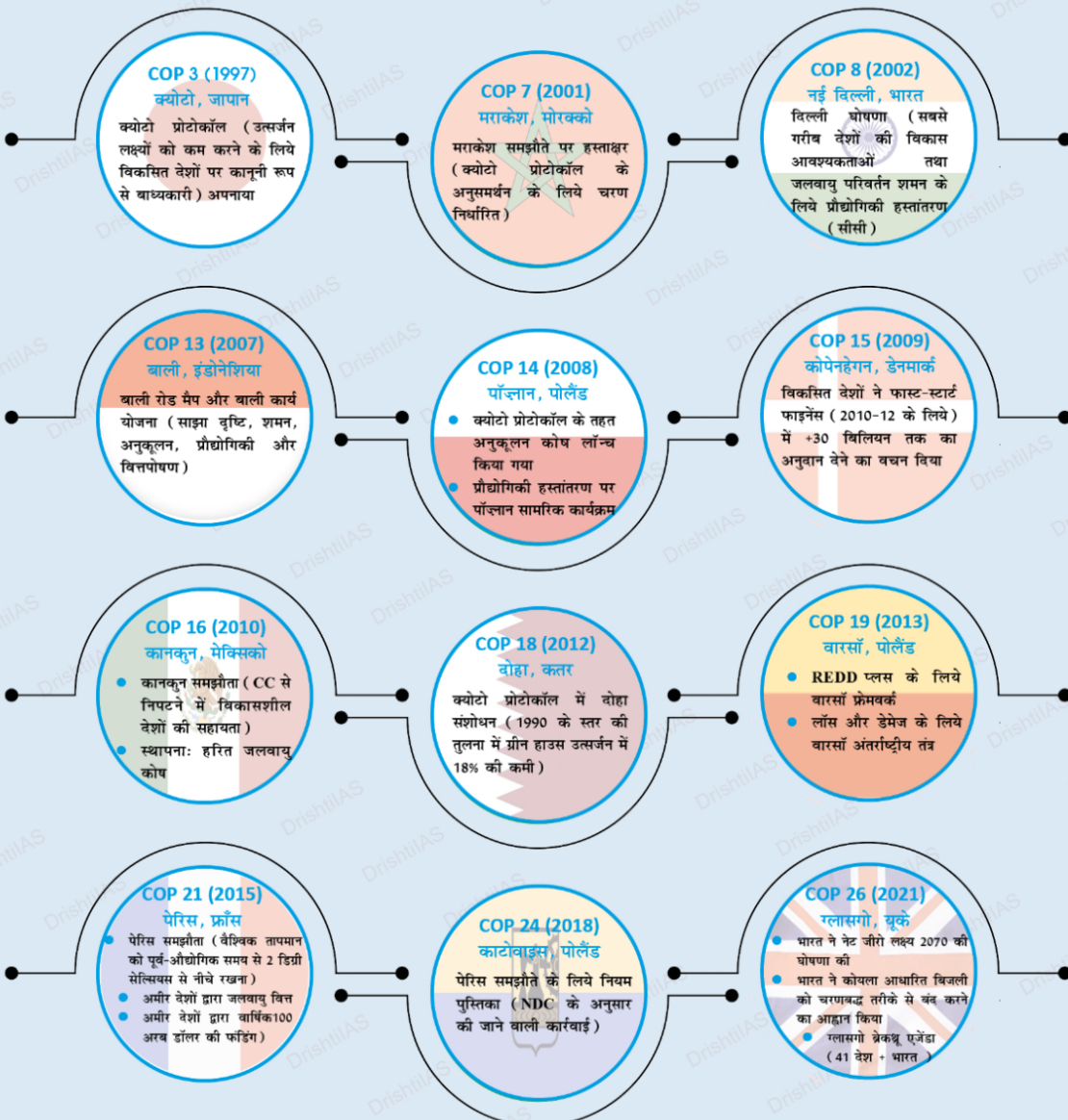
UNFCCC

कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP)

कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज:

- UNFCCC की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था
- प्रत्येक वर्ष बैठक होती है (जब तक कि पक्षकार अन्यथा निर्णय न लें)
- बॉन, सचिवालय में बैठक (जब तक कि कोई पार्टी सत्र की मेजबानी करने की पेशकश नहीं करती)
- पहला सीओपी- बर्लिन, जर्मनी में आयोजित (1995)

COPs और उनके प्रमुख परिणाम



COP 27 (2022)

शर्म-अल-शेख, मिश्र

- लॉस और डेमेन फंड
- पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिये USD 3.1 बिलियन की योजना

- जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों के लिये G7 के नेतृत्व वाली 'ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी'
- अफ्रीकी कार्बन बाजार पहल
- जल अनुकूलन और लचीलापन (AWArE) पहल के लिये कार्रवाई
- मैग्नेब एलायंस (भारत के साथ साझेदारी में)
- भारत की दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति

- 50% नयिम, जसि ऐतहिासकि रूप से सरवोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है, यह नरिदेश देता है कभिरत में नौकरयिों या शकिषा के लयि आरकषण कुल सीटों या पदों के 50% से अधकि नही होना चाहयि ।
- प्रारंभ में वर्ष 1963 के एम.आर. बालाजी मामले में सात-न्यायाधीशों की पीठ दवारा स्थापति, आरकषण को संवैधानकि ढाँचे के तहत एक “अपवाद” या “वशिष प्रावधान” माना जाता था, जसिसे उपलब्ध सीटों की अधकितम 50% तक सीमति थी ।
- हालाँकि आरकषण की समझ वर्ष 1976 में वकिसति हुई जब यह स्वीकार कयिा गया क आरकषण कोई अपवाद नही है बल्कि सिमानता का एक घटक है । परपिरेकष्य में इस बदलाव के बावजूद 50% की सीमा अपरविरतति रही ।
- वर्ष 1990 में मंडल आयोग मामले में नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने 50% की सीमा की फरि से पुष्टि की और कहा कयिह एक बाध्यकारी नयिम है, न क केवल वविक का मामला है । हालाँकयिह अपवाद के बनिा कोई नयिम नही है ।
- राज्य हाशयि पर और सामाजकि मुखयधारा से बाहर कयि गए समुदायों को आरकषण प्रदान करने के लयि शिषिट परस्थितयिों में सीमा को पार कर सकते हैं, वशिष रूप से भौगोलकि स्थति के बावजूद ।
- इसके अलावा, सरवोच्च न्यायालय की 103वें संवैधानकि संशोधन की हालयिा पुष्टि आरथकि रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लयि

अतः 10% आरक्षण को मान्य करती है।

- इसका मतलब है कि **50% की सीमा केवल गैर-EWS आरक्षण पर लागू** होती है और राज्यों को EWS आरक्षण सहित कुल 60% सीटें/पद आरक्षण करने की अनुमति है।

■ **अन्य राज्य सीमा पार कर रहे हैं:**

- अन्य राज्य जो EWS कोटा को छोड़कर भी पहले ही 50% की सीमा को पार कर चुके हैं, वे हैं **छत्तीसगढ़ (72%), तमिलनाडु (69%)**, वर्ष 1994 के अधिनियम के तहत संविधान की नौवीं अनुसूची के तहत संरक्षित और कई उत्तर-पूर्वी राज्य जसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मजोरम और नगालैंड (80% प्रत्येक) शामिल हैं।
- लक्षद्वीप में **अनुसूचित जनजातियों के लिये 100% आरक्षण** है।
- **महाराष्ट्र और राजस्थान** के पछिले प्रयासों को न्यायालयों ने खारिज कर दिया है।

संविधान और आरक्षण

- **77वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1995:** इंदरा साहनी मामले में कहा गया था कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों में होगा, पदोन्नति में नहीं।
- हालाँकि संविधान में अनुच्छेद 16(4A) को जोड़ने से राज्य को SC/ST कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के प्रावधान करने का अधिकार मिला गया, अगर राज्य को लगता है कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **81वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2000:** इसमें अनुच्छेद 16(4B) पेश किया गया, जिसके अनुसार किसी विशेष वर्ष का रक्त SC/ST कोटा, जब अगले वर्ष के लिये आगे बढ़ाया जाएगा, तो उसे अलग से माना जाएगा एवं उस वर्ष की नियुक्ति रक्तियों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।
- **85वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2001:** इसमें पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है जस जून 1995 से पूर्वव्यापी प्रभाव से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के लिये 'पारिणामिक वरिष्ठता' के साथ लागू किया जा सकता है।
- **संविधान में 103वाँ संशोधन (2019): EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिये 10% आरक्षण।**
- **अनुच्छेद 335:** इसके अनुसार संघ या राज्य के कार्यों से संसक्त सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियों करने में प्रशासनिक प्रभावशीलता को बनाए रखते हुए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जातियों के सदस्यों की मांगों को पूरी तरह से ध्यान में रखा जाना चाहिये।

आगे की राह

- न्यायालयों को वकिसति सामाजिक गतिशीलता, समानता सिद्धांतों तथा बदलते सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य पर विचार करते हुए **50% आरक्षण सीमा का पुनर्मूल्यांकन** करना चाहिये।
- भौगोलिक सीमाओं के बावजूद, ऐतिहासिक क्षति का सामना करने वाले समुदायों के लिये व्यापक मानदंडों को शामिल करने के लिये सामाजिक बहिष्कार से परे अपवादों का विस्तार करने पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है।
- **मौजूदा आरक्षण नीतियों की वसितृत समीक्षा** करना, उनकी प्रभावशीलता, प्रभाव एवं वर्तमान सामाजिक आवश्यकताओं के साथ संरेखण करना।

वेब ब्राउज़र

क्रिप्टो परसिंपत्त भिध्यस्थों के बारे में FSB की चर्चाएँ